



Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 05 मई, 2022

ग्रीन हाइड्रोजन पर भारत-जर्मनी समझौता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोलज़ ने हरति एवं सतत् विकास साझेदारी की स्थापना के लिये संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किये। इसका लक्ष्य द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग में वृद्धि करना और जलवायु संरक्षण की दशा में कार्रवाई में तेज़ी लाना है। इस साझेदारी के तहत जर्मनी ने भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं में 10 बिलियन यूरो के निवेश की अग्रिम प्रतिबद्धता जताई है। यह राशि वर्ष 2030 तक निवेश की जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन पर भारत-जर्मनी समझौता ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग, भंडारण व वितरण में सहयोग को मज़बूत करने के लिये एक "इंडो-जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स" की स्थापना करेगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन हरति हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ग्रीन हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पृथक करके उत्पादित किया जाता है।

नीतगित रेपो दर में 40 आधार अंकों की बढ़ोतरी

भारतीय रज़िर्व बैंक ने नीतगित रेपो दर में 40 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर 4.4 प्रतिशत हो गई है। यह वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। वर्तमान आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में वृद्धि का निर्णय लिया है। इससे मुद्रास्फीति को अपेक्षित स्तर तक बनाए रखने में मदद मिलेगी। मार्च में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति सात प्रतिशत तक पहुँच गई जिसका मुख्य कारण वैश्विक खाद्य मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि होना था। रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक (भारत के मामले में भारतीय रज़िर्व बैंक) किसी भी तरह की धनराशि की कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को धन देता है। इस प्रक्रिया में केंद्रीय बैंक प्रतिभूति खरीदता है। बढ़ी हुई मुद्रास्फीति को कम करने और भू-राजनीतिक तनाव के प्रभाव से निपटने के लिये नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.50 प्रतिशत कर दिया गया है।

मॉरसे डू फलिम् समारोह

फ्रांस में कान फलिम् महोत्सव के साथ आयोजित आगामी मारशे डू फलिम् में भारत सम्मानित राष्ट्र होगा। महोत्सव का आयोजन 17 मई, 2022 से शुरू होगा। फ्रांस और भारत अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा तथा राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रों के साथ उनकी बैठक से यह आयोजन और भी महत्त्वपूर्ण हो गया है। इस महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक पृष्ठभूमि में भारत को कान फलिम् समारोह में मारशे डू फलिम् में सम्मानित राष्ट्र के रूप में चुना गया है। 'कान नेक्स्ट' में भी भारत को सम्मानित राष्ट्र का दर्जा दिया गया है, जिसके अंतर्गत ऑडियो-विज़ुअल उद्योग में पाँच नए स्टार्ट-अप को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इस महोत्सव में भारत की ओर से आर. माधवन द्वारा निर्मित फलिम् रॉकेटरी का वर्ल्ड प्रीमियर भी आकर्षण का केंद्रबिंदु होगा।

सरकार ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट, 2020 जारी की

केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट, 2020 जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में 2.48 करोड़ जन्म पंजीकृत किये गए जो वर्ष 2020 में घटकर 2.42 करोड़ हो गए। यह जन्म दर में लगभग 2.40 प्रतिशत की कमी दर्शाती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2019 में पंजीकृत मृत्यु के मामलों की संख्या 76.40 लाख से बढ़कर वर्ष 2020 में 81.20 लाख हो गई जो 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। कुल पंजीकृत मौतों में लगभग 60 प्रतिशत पुरुष और लगभग 40 प्रतिशत महिलाएँ थीं। कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों जैसे- महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, नगालैंड, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, सिकिम, पंजाब, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा असम में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में मृत्यु दर में वृद्धि दर्ज की गई। इस बीच मणिपुर, चंडीगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पुद्दुचेरी, अरुणाचल प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में मृत्यु दर में कमी देखी गई।

